

रजिस्टर्ड नं ० HP/13/SML/2002.



## राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

शिमला, मंगलवार, 22 अक्टूबर, 2002/30 शाश्वत, 1924

## हिमाचल प्रदेश सरकार

## शहरी विकास विभाग

श्रद्धिसंचालना

शिमला-2, 8 अक्टूबर, 2002

संख्या एल ००८०३ी ०-डी( १ ) ३/९६.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९९४ (१९९४ का १३) की धारा १३ की उप-धारा (४) और धारा २३ की उप-धारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ

2028

ग्रामाधारण राज्यपद, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्टूबर, 2002/30 अधिवन, 1924

वा प्रदोग करने वृए नगरपालिका परियदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा सदस्यों के मानदेय एवं भत्ते 1-10-2002 से निम्ननिवित दरों से बढ़ाने/प्रदान करने के महंग आदेश देते हैं :—

पद	मानदेय प्रतिमाह	भत्ते प्रतिमाह
1. नगरपालिका परियदें :		
( 1 ) अध्यक्ष	₹ 0 1250/-	—
( 2 ) उपाध्यक्ष	₹ 0 1000/-	—
( 3 ) सदस्य	—	₹ 0 400/- ₹ 0 200/- की जगह।
2. नगर पंचायतें :		
( 1 ) अध्यक्ष	₹ 0 750/-	—
( 2 ) उपाध्यक्ष	₹ 0 650/-	—
( 3 ) सदस्य	—	रुपए 100/- प्रति बैठक अधिक से अधिक चार बैठकें प्रतिमाह रुपए 50/- प्रति बैठक की जगह।

( 2 ) इस मे इस विभाग के अधिमूक्ता मर्या पल 04म 0जी 0-डी ( 1 ) 3/96, दिनांक 24-7-1997 का अनिकम्म किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
सचिव।

## URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th October, 2002

No. LSG-D(1)3/96.—In exercise of the powers vested in him under sub-section (4) of section 13 and sub-section (3) of section 23 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to enhance/fix the rates of

प्रसाधारण राज्यपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्टूबर, 2002/30 आश्विन, 1924

2029

Honorarium and allowances to the Presidents/Vice Presidents and members of the Municipal Councils and Nagar Panchayts in Himachal Pradesh with effect from 1-10-2002 :—

Designation	Honorarium allowed per month	Allowances allowed per month
<b>1. Municipal Councils :</b>		
Presidents	Rs. 1250/-	—
Vice-Presidents	Rs. 1000/-	—
Members	—	Rs. 400/- instead of Rs. 200/-.
<b>2. Nagar Panchayats :</b>		
Presidents	Rs. 750/-	—
Vice-Presidents	Rs. 650/-	—
Members	—	Rs. 100/- per sitting fee subject to a maximum of four sittings in a month instead of Rs. 50/- per sitting.

This supersedes the earlier notification No. LSG-D (1)3/96, dated 24-7-1997.

By order,

Sd/-  
Secretary.

